



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 151] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 17, 1980/चैत्र 28, 1902  
No. 151] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 17, 1980/CHAITRA 28, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1980

का.आ. 262(अ)/18 च ख/आई डी आर ए/80.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 277(अ)/18 च ख/आई डी आर ए/78, तारीख 20 अप्रैल, 1978 (जिसे इसमें आगे उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा, केंद्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रदत्त सभी संविदाओं, संपत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों और अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न जो बैंको और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित है) जिनके मेसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर की (1) मेसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर (2) मेसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, पांडिचेरी (3) मेसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, नएनी (4) मेसर्स स्वदेशी काटन मिल्स, मऊनाथभंजन, (5) मेसर्स उदयपुर काटन मिल्स उदयपुर और (6) मेसर्स रायबरेली टेक्स्टाइल मिल्स, राय बरेली नामक औद्योगिक उपक्रम पक्षकार हैं जो ऐसे औद्योगिक उपक्रमों को लागू हो सकती

है, प्रवर्तन ऐसी तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व तदधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली सभी बाध्यताएँ और दायित्व उक्त अवधि तक निलम्बित रहेंगे ;

और उक्त आदेश की अस्तित्वाधि 20 अप्रैल, 1980 तक, जिसमें यह तारीख भी है, बढ़ा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अस्तित्वाधि एक वर्ष तक और बढ़ा दी जानी चाहिए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 ख ख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अस्तित्वाधि 20 अप्रैल, 1981 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और बढ़ाती है ।

[फा. सं. 3(6)/78. सी. यू. एस.]

ब. राय, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

#### ORDER

New Delhi, the 17th April, 1980

**S.O. 262(E)/18FB/IDRA/80.**—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development), No. S.O. 277(E)/18FB/IDRA/78, dated the 20th April, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards standing orders or other instruments, in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions), to which the industrial undertakings known as (i) M/s. Swadeshi Cotton Mills, Kanpur, (ii) M/s. Swadeshi Cotton Mills, Pondicherry, (iii) M/s. Swadeshi Cotton Mills, Naini, (iv) M/s. Swadeshi Cotton Mills, Mounath Bhanjan, (v) M/s. Udaipur Cotton Mills, Udaipur and (vi) M/s. Rae Bareilly Textile Mills, Rae Bareilly of Messrs Swadeshi Cotton Mills Company Limited, Kanpur, are parties or which may be applicable to such industrial undertakings shall remain suspended for a period of one year from such date and that all the obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period ;

And whereas the duration of the said Order was extended upto and inclusive of the 20th April, 1980 ;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order for a further period upto and inclusive of the 20th April, 1981.

[File No. 3(6)/78 Cus.]

B. ROY, Jt. Secy.